रक्षा मंत्रालय
MINISTRY OF
DEFENCE
सत्यमेव जयते
वर्षों में
रक्षा सुधार
अगस्त 2023
WWW.MOD.GOV.IN

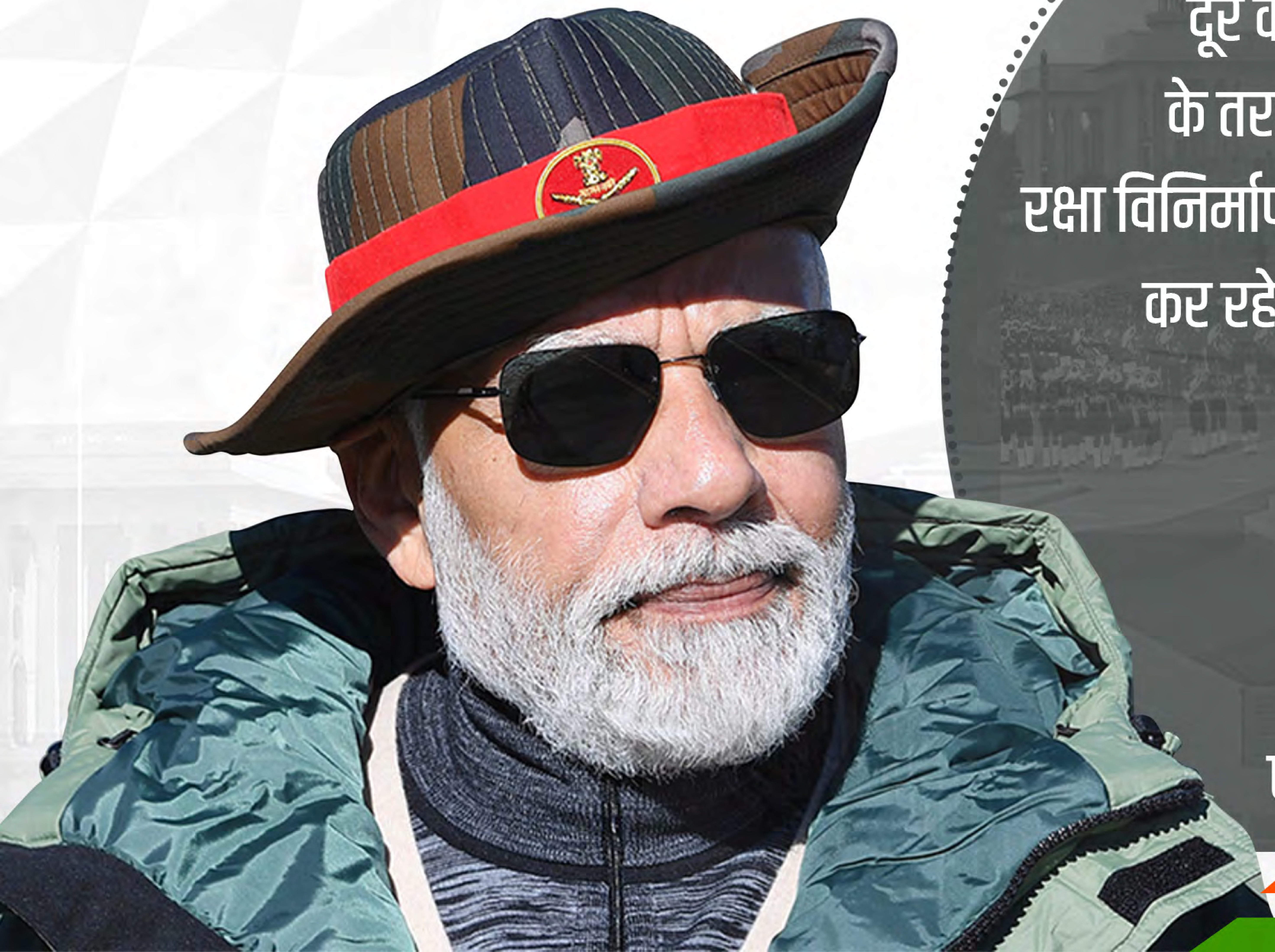

आज का भारत तेज़ सोचता है,
दूर की सोचता है और एक फाइटर पायलट
के तरह तुरंत एक्शन लेता है। हम सबसे बड़े
रक्षा विनिर्माण देशों में शामिल होने के लिए तेज़ी से प्रगति
कर रहे हैं, जिसमें हमारा निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण
भूमिका निभा रहा है।

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
एरो इंडिया 2023 बेंगलूरु, कर्नाटक

भारत सिर्फ असेंबली
वर्कशॉप बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि
हमारा लक्ष्य है कि हम मेक इन इंडिया के द्वारा
वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और समृद्धि के लिए निर्माण
कार्य करें।

रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह,
एरो इंडिया 2023 बेंग्लूरू, कर्नाटक

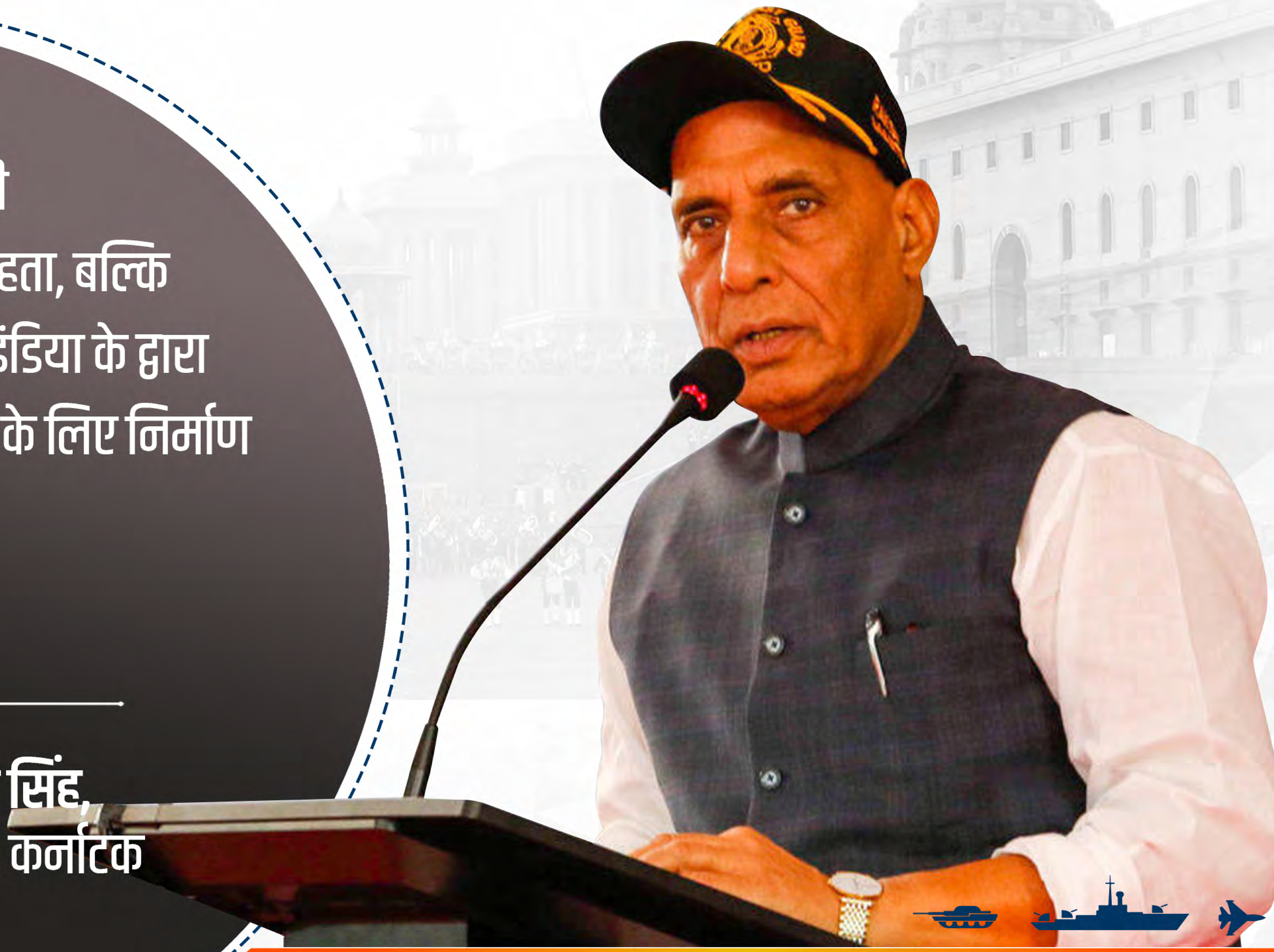

भारत रक्षा विनिर्माण
और हथियारों के निर्यात में अग्रणी
बन रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की
दिशा में हमारी सैन्य शक्ति मज़बूत
हो रही है।

रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट,
राष्ट्रीय रक्षा एमएसएमई कॉन्क्लेव
और प्रदर्शनी सितंबर 2022, कोटा,
राजस्थान

सुदृढ़ रक्षा, आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र

01 असाधारण नवाचारों और सैन्य सुधारों के नौ वर्ष।

02 'अग्निपथ' योजना तकनीक-प्रेमी युवा और भविष्य के लिए तैयार सशस्त्र बलों के निर्माण के लिए शुरू की गई।

03 आईएनएस विक्रांत और एलसीएच प्रचंड ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को धारदार बनाया।

04 स्वदेशी जहाज़ और पनडुब्बियां, नौसेना की शक्ति को और धारदार बनाती हैं।

05 'मेक इन इंडिया' टैंक, मिसाइल और हैंड ग्रेनेड से लैस सेना।

06 रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि - वैश्विक मंच पर भारतीय कंपनियों का उदय।

07 सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर।

08 नई सड़कों और पुलों से सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार।

अग्निपथ
योजना

अग्निपथ योजना - एक प्रमुख परिवर्तनकारी सुधार

01 अग्निपथ देशभक्त और प्रेरित युवाओं को चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है।

02 अग्निपथ सशस्त्र बलों का प्रोफाइल युवा और गतिशील बनाता है।

03 जोखिम, कठिनाई भत्ते और एक बार 'सेवा निधि' पैकेज के साथ आकर्षक मासिक पैकेज।

04 19,000 अग्निवीर भारतीय सेना में प्रशिक्षण पा रहे हैं।

05 ओडिशा के आईएनएस चिल्का में आयोजित भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के पहले बैच की 272 महिलाओं सहित 2,585 अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड।

06 कर्नाटक के बेलगावी में भारतीय वायु सेना में शामिल हुए 2,675 अग्निवीरवायु के पहले बैच की पासिंग आउट परेड।

रक्षा में आत्मनिर्भरता

रक्षा में आत्मनिर्भर
साकार हो रहा एक सपना

01 **सशस्त्र बलों की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची:** सेवाओं की चार सूचियां अधिसूचित की गईं, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग को अपनी डिज़ाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके 400 से अधिक वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम बनाया गया।

02 **रक्षा पीएसयू की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची:** रक्षा पीएसयू द्वारा आयात को कम करने के लिए 4,600 से अधिक वस्तुओं की चार सूचियां अधिसूचित की गईं।

03 रक्षा अनुसंधान एवं विकास के द्वार उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिए गए हैं जिनके लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% निर्धारित किया गया है।

04 इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों पर उद्योग आधारित डिज़ाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख प्लेटफॉर्मों की पहचान की गई है। 14 प्लेटफॉर्म मेक-I श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसके अलावा दो स्पेशल पर्पज़ व्हिकल मॉडल मेक II और iDEX के तहत आते हैं।

05 रक्षा मंत्री द्वारा जुलाई 2022 में "AI इन डिफेंस" प्रदर्शनी में 75 नव विकसित AI उत्पादों/प्रौद्योगिकी को लॉन्च किया गया था।

06 जुलाई 2022 में 'एआई इन डिफेंस' प्रदर्शनी में रक्षा मंत्री द्वारा 75 नव-विकसित एआई उत्पादों प्रौद्योगिकियों को लॉन्च किया गया था।

रक्षा निर्यात
सुदृढ़ घरेलू रक्षा उद्योग

01 **रक्षा निर्यात में 23 गुना वृद्धि:** रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-2014 में 686 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 16,000 करोड़ तक, लगभग 85 देशों में यह निर्यात पहुंचा।

02 लगभग 100 स्वदेशी कंपनियों द्वारा डोर्नियर-228, आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्ज़, रडार्ज़, सिम्युलेटर, बख़्तरबंद वाहन आदि जैसे विमानों सहित प्रमुख प्लेटफार्मों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्यात किया जा रहा है।

03 जुलाई 2022 में फिर से भौगोलिक क्षेत्रों/देशों की सूची को संशोधित किया गया और सात नवगठित डीपीएसयू में आवंटित किया गया।

गत पांच वर्षों के दौरान रक्षा निर्यात (करोड़ रुपये में)

कुल निर्यात मूल्य

2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (06.03.2023 तक)
4,682	10,746	9,116	8,435	12,815	16,000 लगभग

- पिछले नौ वर्षों में रक्षा आयात बनाम निर्यात के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

वर्ष	2013-14	2021-22
आयात मूल्य (पूंजी + राजस्व)	41,198.61	50,061.67
निर्यात मूल्य	1153	12815
अनुपात (आयात और निर्यात)	35.73	3.90

(करोड़ रुपये में)

सृजन पोर्टल

01 रक्षा क्षेत्र के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) और सशस्त्र बलों के लिए एक ग़ैर लेन-देन ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म।

02 मार्च 2023 तक सृजन पोर्टल पर 7282 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया, जहां सार्वजनिक तौर पर 32, 000 से अधिक आइटम उपलब्ध हैं।

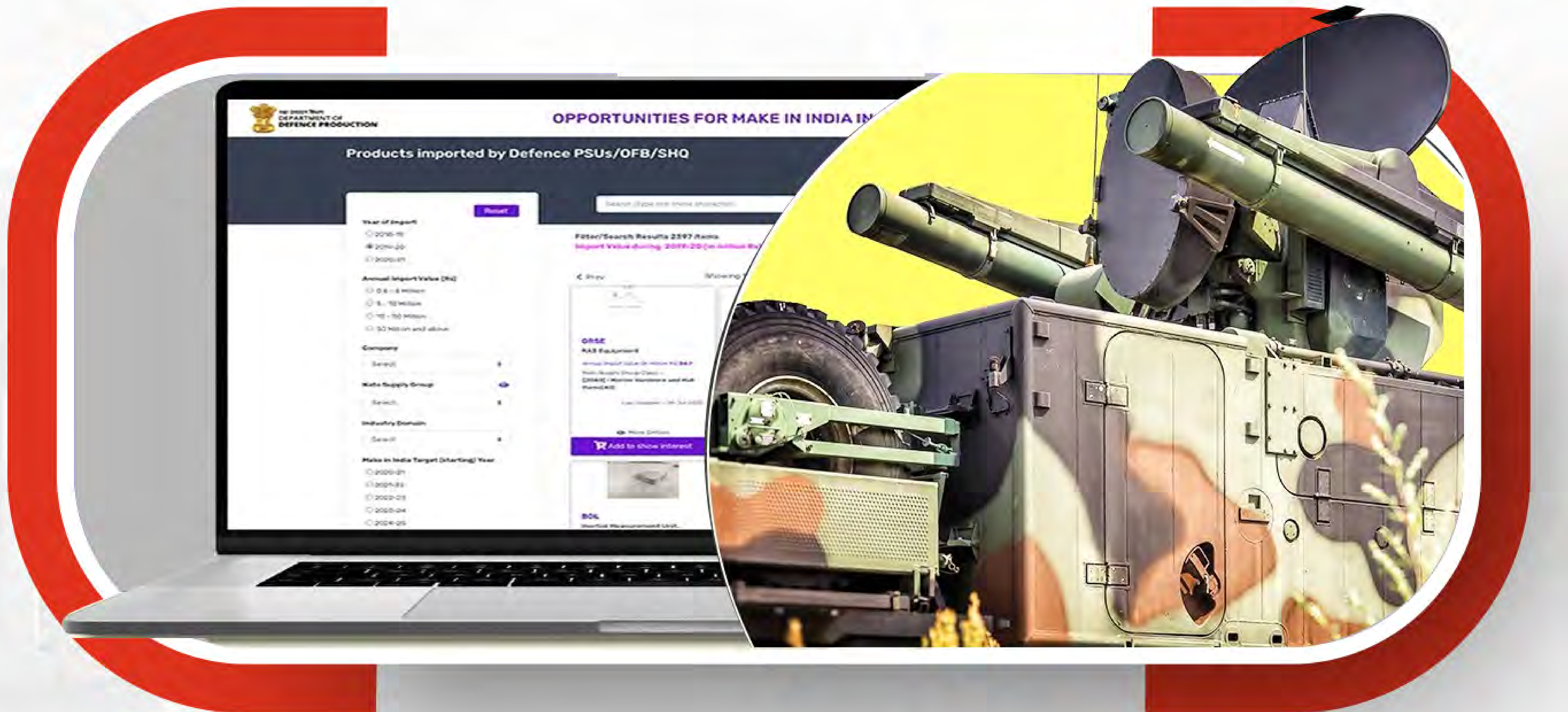

रक्षा औद्योगिक गलियारे

उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में

01 रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं।

02 वर्ष 2024-25 तक कुल 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।

03 दोनों रक्षा औद्योगिक गलियारों को प्रधानमंत्री के 'गति शक्ति' राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया गया है।

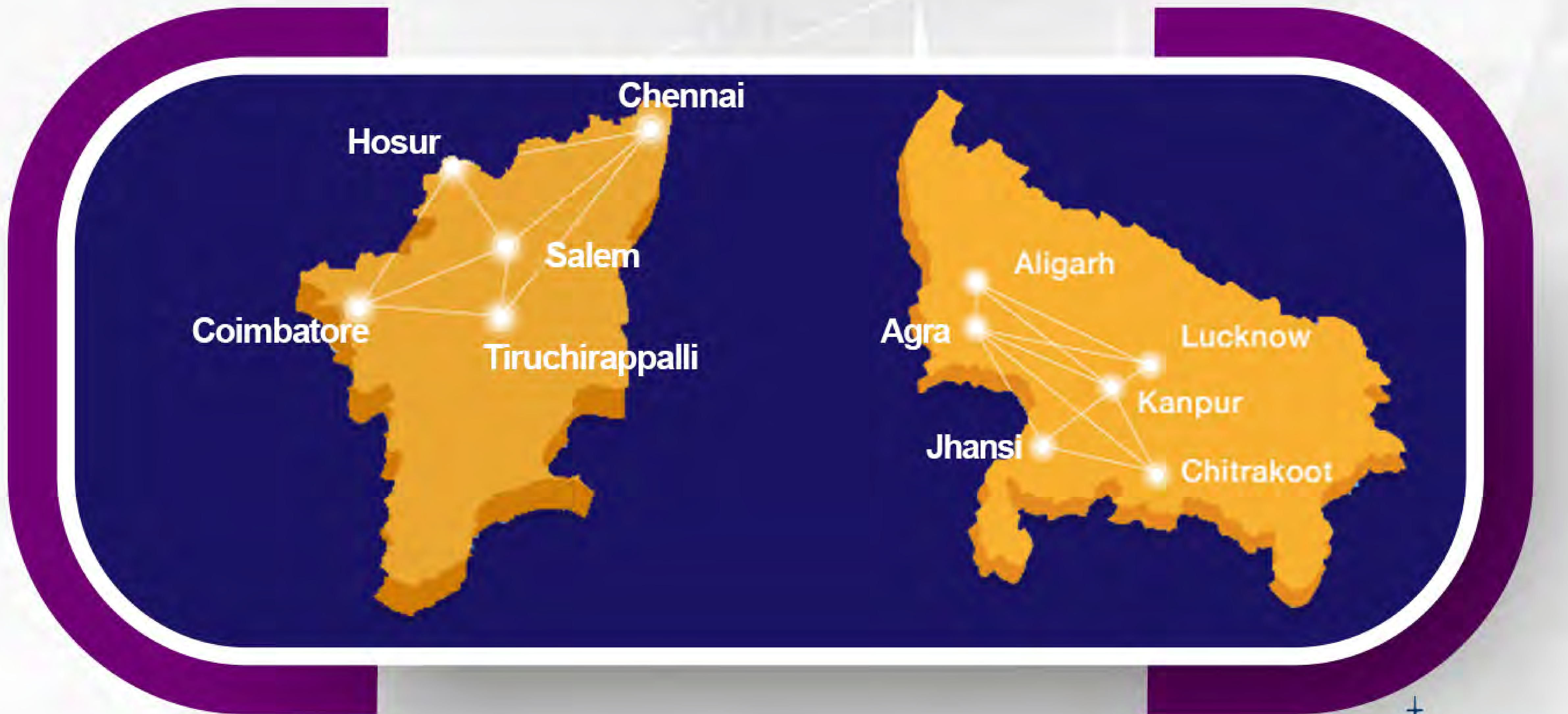

iDEX रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार

01 रक्षा क्षेत्र में सह-निर्माण और सह-विकास प्रदान करने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।

02 रक्षा स्टार्टअप के क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए iDEX देश में रक्षा और एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के निर्माण की परिकल्पना करता है।

03 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजिस (डीएलएससी) के नौ चरणों का समापन हुआ, जिनमें नवोन्वेषक से 8000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।

04 iDEX के अंतर्गत विकसित 14 उत्पादों को सरकार द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति (AON) प्रदान की गई थी।

05 अब तक 250 से अधिक अनुबंधों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

06 पांच वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सरकार ने iDEX को 498.78 करोड़ रुपये के बजट की मंज़ूरी दी है।

रक्षा अधिग्रहण

' मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड '

01 स्वदेशीकरण पर बल देने के साथ 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) आरंभ की गई थी। इसके लक्ष्य:

- उपकरणों के स्वदेशी डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण पर संवर्धित पर अधिक बल दिया जाना।
- अधिग्रहण प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- सर्वोत्तम उपकरणों के पारदर्शी और समय पर चयन के लिए निगरानी तंत्र को संस्थागत बनाना।
- भारतीय तटरक्षक बल और तीनों सेनाओं की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की ख़रीद को स्वदेशी स्तर पर पूरा किया जाएगा।
- घरेलू उद्योग पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए इंटीग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी की आवश्यकता समाप्त कर दी गई।

रक्षा अधिग्रहण

02 निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना

- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना
- सैन्य सेवाओं और भारतीय तट रक्षक के आधुनिकीकरण से संबंधित सभी आवश्यकताओं की स्वदेशी सोर्सिंग।
- वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजी अधिग्रहण के लिए 2.71 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता को मंज़ूरी (AoN) दी गई। 99% क्रय भारतीय उद्योगों से किया जाएगा।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) और स्टार्ट-अप के लिए मार्गदर्शन।
- विदेशी निर्माताओं को भारत में इकाइयों को स्थापित करने और स्थानीय भागीदारों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) और मेक II के माध्यम से पूंजी अधिग्रहण।

- 01 अप्रैल, 2014 और 31 मार्च, 2023 के बीच सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 6.02 लाख करोड़ रुपये के 448 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए।

सैन्य सेवा	अनुबंधों की संख्या	आसन्न लागत
भारतीय सेना	155	1.51 लाख करोड़ रुपये
भारतीय नौसेना	196	1.96 लाख करोड़ रुपये
भारतीय वायु सेना	91	2.42 लाख करोड़ रुपये
भारतीय तटरक्षक बल	10	2.42 लाख करोड़ रुपये

- पूंजी अधिग्रहण मामले की सभी श्रेणियों में वांछित स्वदेशी सामग्री प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।
- पहली बार, दो रक्षा प्लेटफार्मों - हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस (एचएएलई) और सी गार्डियन एमक्यू -9 बी को लीज़ समझौतों के तहत ख़रीदा गया, कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी संचालित मॉडल के अंतर्गत जनरल एटॉमिक्स, यूएसए से ख़रीदा गया है।
- भारतीय निजी विक्रेताओं के लिए बड़े रक्षा प्लेटफार्मों पर सीमा शुल्क की छूट।
- ख़तरे की आशंका , परिचालन चुनौतियों और तकनीकी परिवर्तनों के आधार पर, सेना को तत्परता की स्थिति में रखने के लिए अत्याधुनिक प्लेटफार्मों/प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण।

सुधारों के पथ पर सशस्त्र बल

A

सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच संयुक्तता और तालमेल को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा सुधार में, सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) और चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस)का पद सृजित किया गया है।

B

डीएमए के तहत, तीन संयुक्त सेवा अध्ययन समूह (जेएसएसजी) सभी आपूर्ति श्रृंखला कार्यों जैसे योजना, ख़रीद, इन्वेंट्री-रख-रखाव, वितरण, निपटान और प्रलेखन को बढ़ाने के लिए सेवाओं के लिए सामान्य लॉजिस्टिक नीतियां विकसित कर रहे हैं।

C

संयुक्त प्रशिक्षण: प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने, एकीकृत करने और तर्कसंगत बनाने के लिए और बुनियादी ढांचे और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, तीनों सेनाओं ने पांच क्षेत्रों में संयुक्त प्रशिक्षण शुरू किया है।

D

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन: ख़रीद की समय-सीमा कम करने, और रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करने के लिए, सशस्त्र सेनाओं को अब व्यग्तिगत स्कीमों के लिए 300 करोड़ रुपये व्यय करने का अधिकार दिया गया है।2015-17 के दौरान यह राशि महज़ 50 करोड़ रुपये थी। राजस्व पक्ष पर, सेनाएं अब 500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे सकती हैं।

सशस्त्र बलों द्वारा प्रमुख ख़रीद

हर काम देश के नाम

भारतीय वायु सेना
आकाश के संरक्षक

- 01 भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों को बेड़े में शामिल किया, दो लड़ाकू स्क्वाड्रनों को पुनर्गठित किया।
- 02 स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के दो स्क्वाड्रन।
- 03 एलसीएच प्रचंड को शामिल किया गया , हमला और हवाई लड़ाकू क्षमता के साथ पहला स्वदेशी मल्टी-रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर।
- 04 बोइंग एएच-64ई अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को शामिल किया गया ।
- 05 बोइंग सीएच-47एफ चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर रणनीतिक एयरलिफ्ट और आपदा राहत क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
- 06 हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण ।
- 07 सी-130जे को शामिल किया गया जिसमें डिजिटल एवियोनिक्स और हेडअप डिस्पले सहित कई आधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

भारतीय वायु सेना
आकाश के संरक्षक

08 हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक क्षमता प्रदान करने के लिए ब्रह्मोस एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलों के साथ एक नया Su-30MKI स्क्वाड्रन।

09 मध्यम दूरी की वायु रक्षा क्षमता के लिए स्वदेशी आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली।

10 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की पहली वितरण योग्य फायरिंग यूनिट सौंपना।

11 उन्नत एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और हथियारों के साथ उन्नत मिराज 2000 लड़ाकू जेट।

भारतीय नौसेना
समुद्र के वीर संरक्षक

01 2014 के बाद से 27 जहाज़ों और 6 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है।

02 भारतीय नौसेना के वर्शिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को डिज़ाइन और कमीशन किया गया। लगभग एक हज़ार एमएसएमई और 500 सहायकों का योगदान इस प्रोजेक्ट में रहा।

03 62 पोतों और एक पनडुब्बी का निर्माणाधीन है। 61 जहाज़ देश में ही बनाए जा रहे हैं।

04 भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 9 वर्षों में, कुल व्यय का औसतन 65% स्वदेशी ख़रीद के लिए उपयोग किया गया था, जिसके निकट भविष्य में 80% तक बढ़ने की उम्मीद है।

05 भारतीय नौसेना गोला-बारूद के 100% स्वदेशीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पारंपरिक गोला-बारूद का 90% तक स्वदेशीकरण किया गया है।

भारतीय सेना

अग्नि क्षमता हुई और धारदार

01 **टी -90 भीष्म:** भारतीय सेना ने टी -90 (भीष्म) मुख्य युद्धक टैंकों की महत्वपूर्ण संख्या हासिल की, जिसने इसकी मारक क्षमता, सुरक्षा और गतिशीलता को बढ़ाया।

02 **एमबीटी अर्जुन एमके 1ए टैंक:** 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, भारतीय सेना ने एमबीटी अर्जुन एमके -1ए टैंक को भी शामिल किया।

03 **असॉल्ट राइफल (एके-203):** एके-203 राइफलें इन-सर्विस इंसास राइफल की जगह लेंगी और इनका निर्माण आईआरआरपीएल, अमेठी (भारत-रूसी संयुक्त जेवी) में किया जा रहा है।

भारतीय सेना

अग्नि क्षमता हुई और धारदार

04 के9 वज्र-टी: स्व-चालित होविट्ज़र्स में उच्च सटीकता और तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताएं हैं। इसके अलावा धनुष एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस), माउंटेड गन सिस्टम (एमएसजी)को भी शामिल किया।

05 अपाचे एएच 64 ई: भारतीय सेना ने स्ट्राइक कोर की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर हासिल किए हैं।

06 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, भारतीय सेना ने बीडीएल से आकाश हथियार प्रणाली (एडब्ल्यूएस) हासिल की है।

07 एम 777 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र्स (यूएलएच) की खरीद की गई है जो उन्नत, हल्के वजन और हेली-पोर्टेबल है।

भारतीय तटरक्षक बल
समुद्र के प्रहरी

01 वायु क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए 16 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) एमके-III को शामिल किया गया है।

02 42 जहाज़ों (27 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, 12 अपतटीय गश्ती जहाज़ों, 02 प्रदूषण नियंत्रण और 01 प्रशिक्षण जहाज़) की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। 06 सहायक नौकाओं और 15 कार्य नौकाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध भी संपन्न हुआ।

03 आईसीजी ने तट और जहाजों से लॉन्चिंग क्षमताओं के साथ 10 मल्टीकॉप्टर ड्रोन हासिल किए।

04 2014 के बाद से, जहाज़ों, हेलीकॉप्टरों, डोर्नियर एयरक्राफ्ट और सेंसर के अधिग्रहण के लिए 13,570 करोड़ रुपये के 10 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

आयुध निर्माण को समन्वित और सक्रिय किया गया

01 अक्टूबर 2021 में सात नए डीपीएसयू के तहत 41 आयुध कारखानों को फिर से संगठित किया गया और अधिक स्वायत्तता दी गई।

02

भारत-रूस संयुक्त उद्यम द्वारा एके-203 असॉल्ट राइफल्स का परीक्षण उत्पादन अमेठी में शुरू हुआ।

डीआरडीओ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास में नवाचार आर एंड डी

01 **नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल (आकाश-एनजी):** नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली आकाश-एनजी मिसाइल का सफल उड़ान, परीक्षण एक भूमि-आधारित मंच से किया गया।

02 **शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम -10 मीटर:** यह एक विस्तृत, पूरी तरह से डेक सड़क मार्ग प्रदान करने वाले एकल अवधि के रूप में अंतराल को पाटने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे सैनिकों की तेज़ी से आवाजाही सुनिश्चित होती है।

03 **अस्त्र:** दृश्य रेंज से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र' को अत्यधिक क़लाबाज़ी करने वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को संलग्न करने और नष्ट करने के लिए विकसित किया गया था।

04 **ब्रह्मोस**

फिलीपींस के साथ अनुबंध

प्राइवेट लिमिटेड (बीएपीएल) ने एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के लिए फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

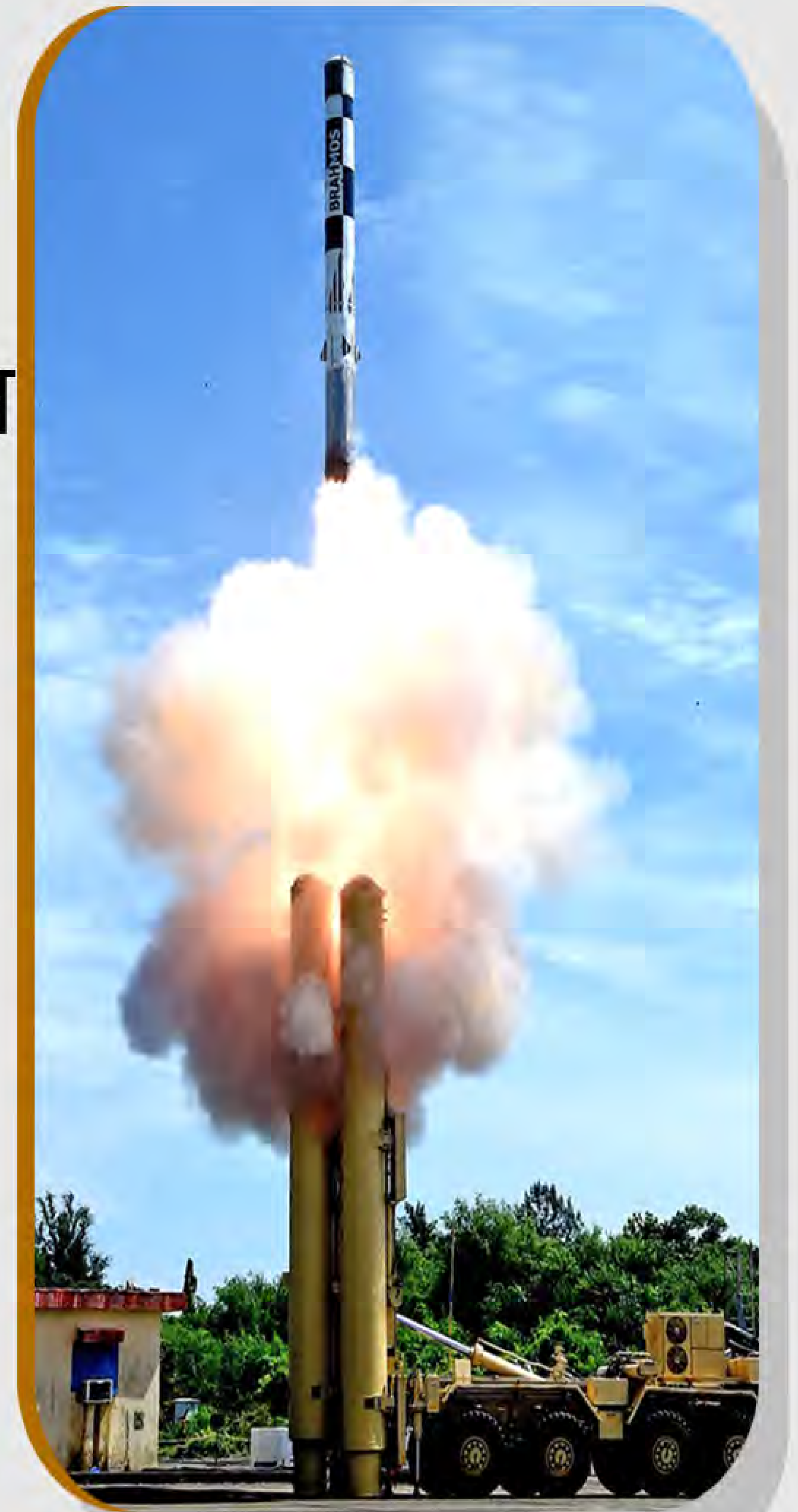

05 **नाग मिसाइल:** तीसरी पीढ़ी की एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम उपयोगकर्ता परीक्षण अक्टूबर 2020 में पोखरण रेंज से किया गया।

पिनाका रॉकेट सिस्टम: नवंबर 2020 में ओडिशा तट से उन्नत पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

06 **क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी:** डीआरडीओ और आईआईटी ने संयुक्त रूप से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाले क्वांटम डिस्ट्रिब्यूशन/वितरण लिंक को विकसित और प्रदर्शित किया है। इसमें सुरक्षा एजेंसी को स्वदेशी तकनीक की मदद से सुगम क्वांटम संचार नेटवर्क को नियोजित करने में सक्षम होंगे।

07 **लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल:** भारतीय नौसेना की वायु रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने के लिए इस प्रणाली (लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल) को डीआरडीओ और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह विभिन्न हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध बिंदु और सुरक्षा क्षेत्र प्रदान कर सकता है।

08 **हेलिना (सेना संस्करण) और ध्रुवस्त्र (वायु सेना संस्करण):** हेलिना और ध्रुवस्त्र तीसरी पीढ़ी के हैं, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च (एलओबीएल) फायर और फॉर्गेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल जो सीधे हिट मोड के साथ-साथ शीर्ष हमले मोड दोनों में लक्ष्य को भेद सकते हैं।

09 **मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल:** स्वदेशी रूप से विकसित कम वज़न, फायर एंड फॉर्गेट मैन पोर्टेबल एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

प्रौद्योगिकी विकास निधि

01

भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का समग्र निधि बनाया गया। विशेषकर एमएसएमई को स्वदेशी रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए।

02

इस निधि का उपयोग डीआरडीओ, सेवाओं और डीपीएसयू द्वारा आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है।

03

टीडीएफ के तहत प्रत्येक परियोजना की लागत 10 करोड़ रुपये तक हो सकती है। उद्योग परियोजना की लागत का 90% तक वित्त पोषण मिल सकता है।

भारतीय उद्योग के लिए डीआरडीओ पेटेंट

01 सभी पेटेंट और प्रासंगिक बौद्धिक प्रकाशन www.drdo.gov.in पर उपलब्ध हैं। इनका उपयोग भारतीय उद्योग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

02 डीआरडीओ के पास उपलब्ध आईपीआर की कुल संख्या 2014 में 596 से बढ़कर 2023 में 2,516 हो गई है।

03 डीआरडीओ ने मई 2023 तक निजी उद्योगों को 1,600 प्रौद्योगिकियां सौंपी हैं।

डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों के लिए विकास सह उत्पादन भागीदार (डीसीपीपी) मॉडल:

01 डीआरडीओ ने मई 2023 तक निजी उद्योगों को 1,600 प्रौद्योगिकियां सौंपी हैं।

02 विकास-से-प्रेरण (इंडक्शन) चक्र की समय-सीमा में कटौती।

03 डीसीपीपी से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के लिए कोई शुल्क नहीं है।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी)

में डिजिटल इंडिया लाना

एमओडी ने अपनी LAN स्थापित की

एमओडी के विभिन्न संगठन डिजिटल हुए

एनसीसी ऑनलाइन

एमओडी पेंशन ऑनलाइन

रक्षा संपदा ऑनलाइन

रक्षा क्षेत्र में साथ व्यापार करने में आसानी

छावनी सेवा ऑनलाइन

कैंटीन विभाग ऑनलाइन हुआ

31
भारतीय सशस्त्र सेना
शांति के प्रहरी
CL-I

शांति के लिए सेना

सर्जिकल स्ट्राइक

01 उरी हमले के 11 दिन बाद भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर, 2016 की रात पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक कर यह कड़ा संदेश दिया था कि सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

02 आतंकवादियों और उनको प्रश्रय देने वालों को भारी नुक़सान पहुंचाया गया, जिसके बाद रूख़ में बदलाव के एक नए युग की शुरुआत हुई।

2019 बालाकोट हवाई हमले

01 भारत ने 26 फरवरी, 2019 को तड़के इंटेलिजेंस आधारित अभियान में बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया।

02 बड़ी संख्या में जैश के आतंकवादियों, ट्रेनर, सीनियर कमांडरों का सफाया किया।

03 यह पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती आतंकवादी हमले के जवाब में किया गया। 14 फरवरी, 2019 को हुए आतंकी हमले में 40 बहादुर सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी।

'रक्षक ' के रूप में सशस्त्र बल

ऑपरेशन गंगा: भारतीय वायु सेना ने अपने सी -17 विमान की 24 उड़ानों के माध्यम से संघर्ष प्रभावित यूक्रेन से 2,457 भारतीय नागरिकों को निकाला।

01

ऑपरेशन दोस्त:
भारतीय सेना फील्ड अस्पताल 2022 में भूकंप से प्रभावित तुर्कीये में 3,600 से अधिक पीड़ितों का इलाज किया। इसने आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान की और 04 प्रमुख सर्जरी, 63 छोटी सर्जरी, 343 छोटे प्रॉसीजर्स किए।

02

ऑपरेशन मैत्री: भारतीय वायुसेना ने 2015 में एक बड़े भूकंप के बाद नेपाल में राहत और बचाव प्रयासों के लिए संपत्ति जुटाई। भारतीय वायुसेना के कई विमानों/हेलीकॉप्टरों ने 1,638 उड़ानें भरीं और 5,973 लोगों को बचाया।

03

ऑपरेशन कावेरी:
एक संयुक्त ऑपरेशन में, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन कावेरी अप्रैल, 2023 के तहत संघर्षग्रस्त सूडान से 3000+ भारतीयों को वापस लाया गया।

04

मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर)

01 **'ऑपरेशन संकल्प ':** 2019 में फुजैरा और ओमान की खाड़ी में टैंकरों पर हमले के मद्देनज़र, भारतीय नौसेना ने होर्मूज़ और खाड़ी क्षेत्र के जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने जहाजों को तैनात किया।

02 **ऑपरेशन समुद्र सेतु-2:** अप्रैल 2021 में, भारतीय नौसेना ने कोविड महामारी के मद्देनज़र चिकित्सा ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका परिवहन शुरू किया।

03 **मिशन सागर:** कोविड-19 महामारी के दौरान हिंद महासागर के तटीय राज्यों और 15 मित्र देशों की सहायता के लिए, भारतीय नौसेना ने जहाज़ों को तैनात किया।

04 **ऑक्सीजन एक्सप्रेस:** कोविड-19 के दौरान लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के द्वीप क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बनाए रखने के लिए नौसेना के जहाज़ों को तैनात किया गया था।

05 भारतीय नौसेना के पी-81 विमान को विभिन्न देशों में कोविड-19 टीकों की 1.5 लाख ख़ुराक पहुंचाने के लिए तैनात किया गया था।

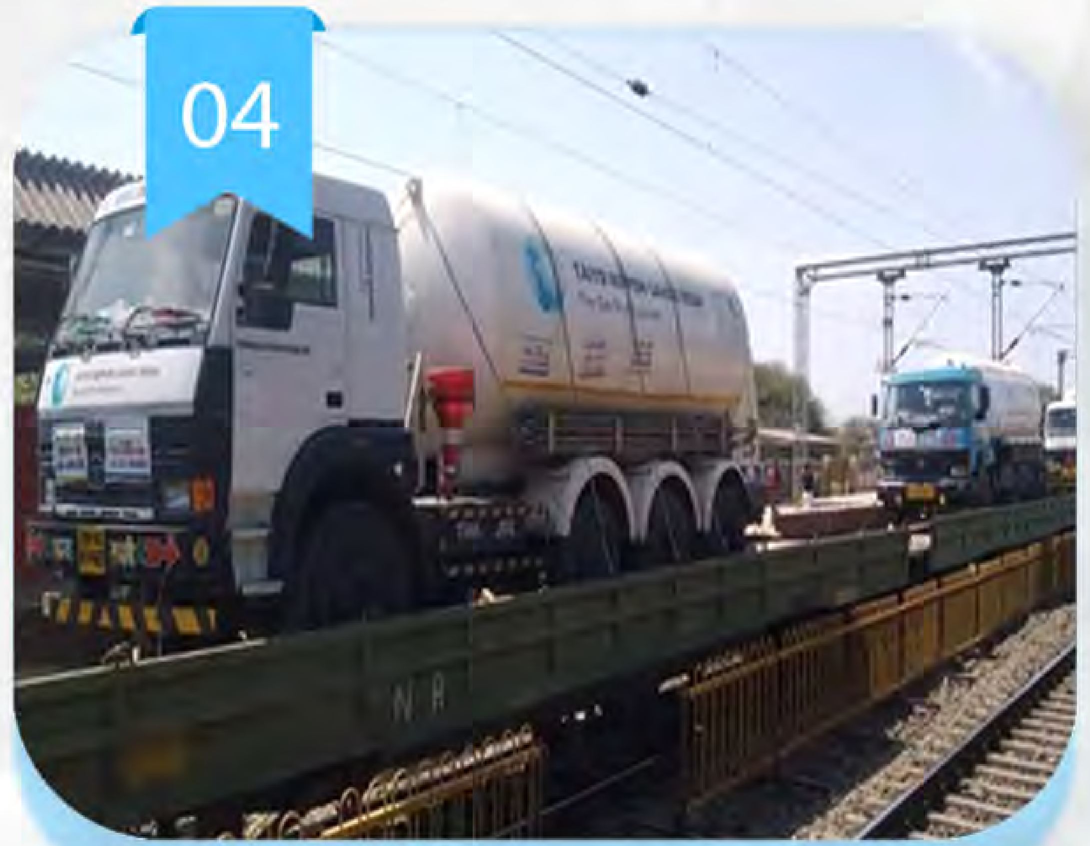

कोविड-19

अदृश्य दुश्मन के ख़िलाफ लड़ाई

2020 में पहली लहर:

01 मिशन वंदे भारत के तहत भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने चीन और अन्य देशों से लगभग 4,200 भारतीयों को निकाला।

01

02 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा कर्मियों द्वारा संचालित संगरोध सुविधाएं, पूरे भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों में स्थापित की गई हैं।

02

03

03 डीआरडीओ और डीपीएसयू ने वेंटिलेटर, सैनिटाइज़र, मास्क और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का निर्माण किया और जो विभिन्न संगठनों को आपूर्ति की।

04 डीआरडीओ ने विभिन्न राज्यों में कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना की।

कोविड-19

अदृश्य दुश्मन के ख़िलाफ लड़ाई

2021 में दूसरी लहर:

01 भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश और विदेश के भीतर ऑक्सीजन कंटेनरों और अन्य चिकित्सा उपकरणों की परिवहन व्यवस्था की।

02 डीआरडीओ, डीपीएसयू और छावनी बोर्डों ने देश भर में कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना की।

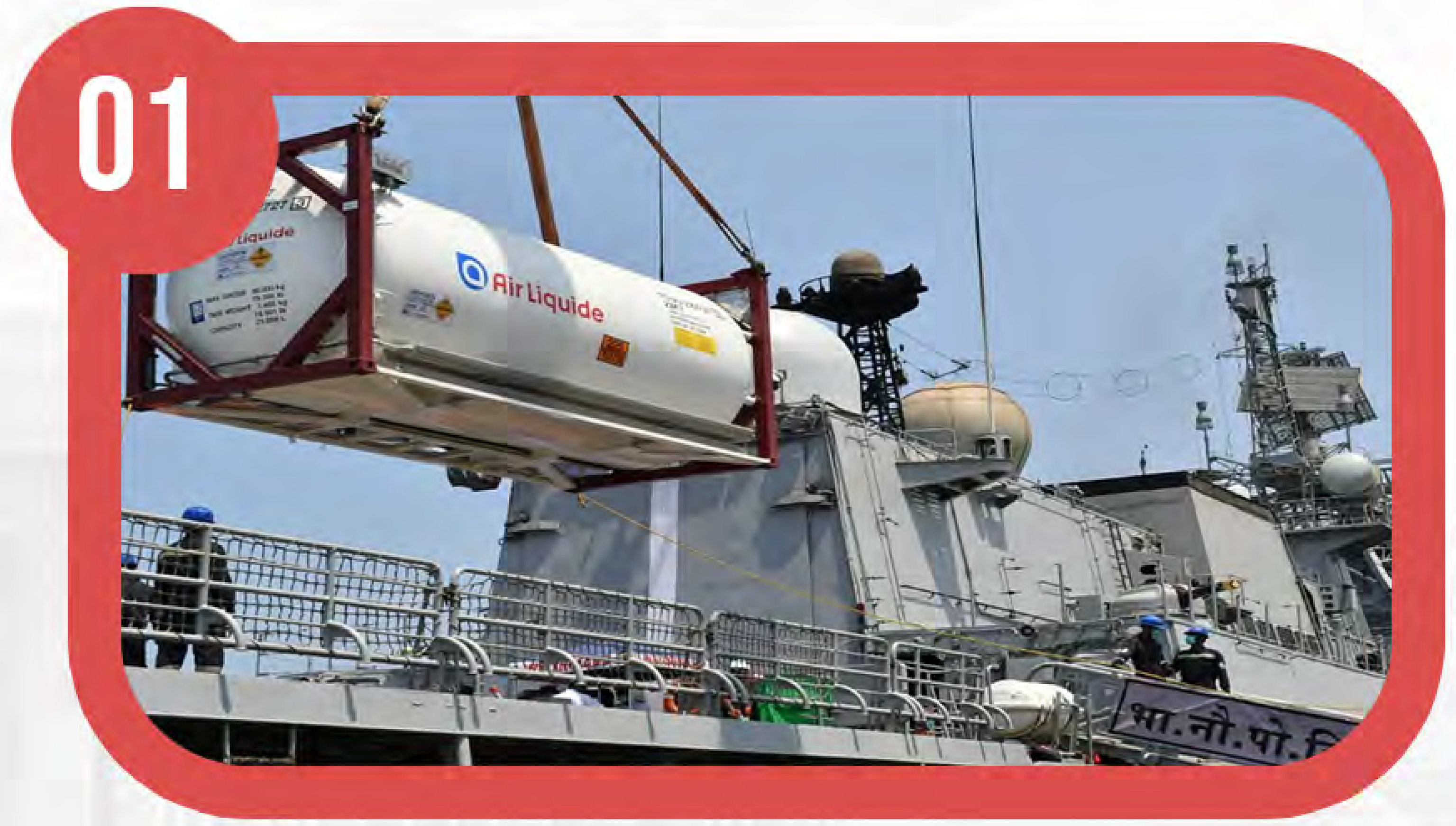

03 डीआरडीओ ने सहायक कोविड थेरेपी, एंटी-कोविड दवा, 2- डिओक्सी, डी-ग्लूकोज़ (2-डीजी) विकसित की।

04 एनसीसी कैडेटों को नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया।

रक्षा क्षेत्र में
नारी शक्ति
KHATRI

सशस्त्र बलों में नारी शक्ति

भारतीय सेना

01 आठ शस्त्र/सेवाओं में लगभग 550 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया।

02 **कर्नल (चयनित ग्रेड)**

कर्नल (चयनित ग्रेड) रैंक के लिए महिला अधिकारियों पर भी विचार किया जा रहा है और उन्हें कमांड नियुक्तियां दी जा रही हैं।

03 **आर्मी एविएशन में महिलाएं**

भारतीय सेना ने वर्ष 2021 से सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में सेवा करने के लिए महिला अधिकारियों के लिए रास्ते भी खोले हैं।

04 83 महिला जवानों के पहले बैच को सैन्य पुलिस कोर में शामिल किया गया।

01

कैप्टन अभिलाषा बराक

आर्मी एविएशन कोर में लड़ाकू एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बनीं।

02

लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी

उन्होंने इतिहास में तब अपना नाम दर्ज करवाया जब वह गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष टुकड़ी (आर्मी सर्विस कोर) का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।

03

कैप्टन शिवा चौहान

दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में कुमार पोस्ट में तैनात होने वाली फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की पहली महिला अधिकारी बनीं।

स्क्वाड्रन लीडर्स

भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह

- फ्लाइंग ऑफिसर (अब स्क्वाड्रन लीडर्स) अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह को पहली तीन महिला लड़ाकू पायलटों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदल दिया है।

01

विंग कमांडर अंजलि सिंह

सैन्य इतिहास में पहली महिला जिन्हें विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में तैनात किया गया है (मॉस्को में भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अटैची)।

02

फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह

राफेल लड़ाकू विमान की भारत की पहली महिला पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने 2022 गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की झांकी में खड़े होकर बढ़ते महिला सशक्तिकरण को दर्शाया।

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना द्वारा मई 2023 तक 58 एसएससी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया।

- **फ्रंटलाइन कॉम्बैट प्लेटफार्मों /बलों में नियुक्ति:** पुरुष अधिकारियों के समान युद्धपोतों पर महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा, महिलाओं को पायलट और नौसेना एयर ऑपरेटर, मार्कोस (समुद्री कमांडो) के रूप में नौसेना विमानन में भी शामिल किया जा रहा है।
- **हेलीकॉप्टरों पर नौसेना वायु संचालन (एनएओ) अधिकारी:** महिला अधिकारियों को विशेषज्ञ एनएओ अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- अशांत समुद्र और कठिन मौसम का सामना करते हुए, छह अधिकारियों की एक टीम ने 254 दिनों में एक स्वदेशी नौका आईएनएसवी तारिणी पर दुनिया की ऐतिहासिक परिक्रमा पूरी की।

लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई

मॉस्को में भारतीय दूतावास
में सहायक नौसेना अटैची के
रूप में नियुक्त किया गया;
विदेश में भारतीय मिशन में
तैनात होने वाली
पहली महिला नौसेना अधिकारी।

अग्निवीर के रूप में महिलाएं: अग्निपथ योजना के हिस्से के रूप में, महिलाओं को 2023 के पहले बैच से ही अग्निवीर के रूप में नामांकित किया गया है।

एनडीए और सैनिक स्कूल में महिलाएं

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दरवाजे खोलने का क्रांतिकारी कदम: जुलाई 2022 में 19 महिला कैडिट्स ने एनडीए में प्रवेश किया, और 19 कैडिट्स के दूसरे बैच ने जनवरी 2023 में प्रशिक्षण शुरू किया।

लड़कियों के लिए सभी सैनिक स्कूल खोलना: जुलाई 2023 तक 33 सैनिक स्कूलों में 1,602 से अधिक लड़कियों को प्रवेश दिया गया है।

01

02

राष्ट्रीय समर स्मारक

हमारे वीरों के पराक्रम को अमर करने वाला

समर स्मारक में **15.5** मीटर लंबा स्तंभ है।

इसमें एक शाश्वत लौ और **16** गोलाकार ग्रेनाइट की दीवारें हैं।

29,760 से अधिक शहीद नायकों के नाम सोने में उत्कीर्ण किए गए हैं।

राष्ट्रीय समर स्मारक

बहादुरों को श्रद्धांजलि

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता के बाद से हमारे सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करने के लिए 25 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया।
- स्वतंत्र भारत के 26,000 से अधिक युद्ध हताहतों का सम्मान करता है।
- युद्ध में शहीद सैनिकों को सम्मानित करने के लिए हर शाम एक परिजन समारोह आयोजित किया जाता है। शहीद सैनिकों शहीदों के परिजनों को अमर लौ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
- इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति जनवरी, 2022 में एनडब्ल्यूएम की शाश्वत लौ में विलीन हो गई।

जीवन को जोड़ती सीमा अवसंरचना

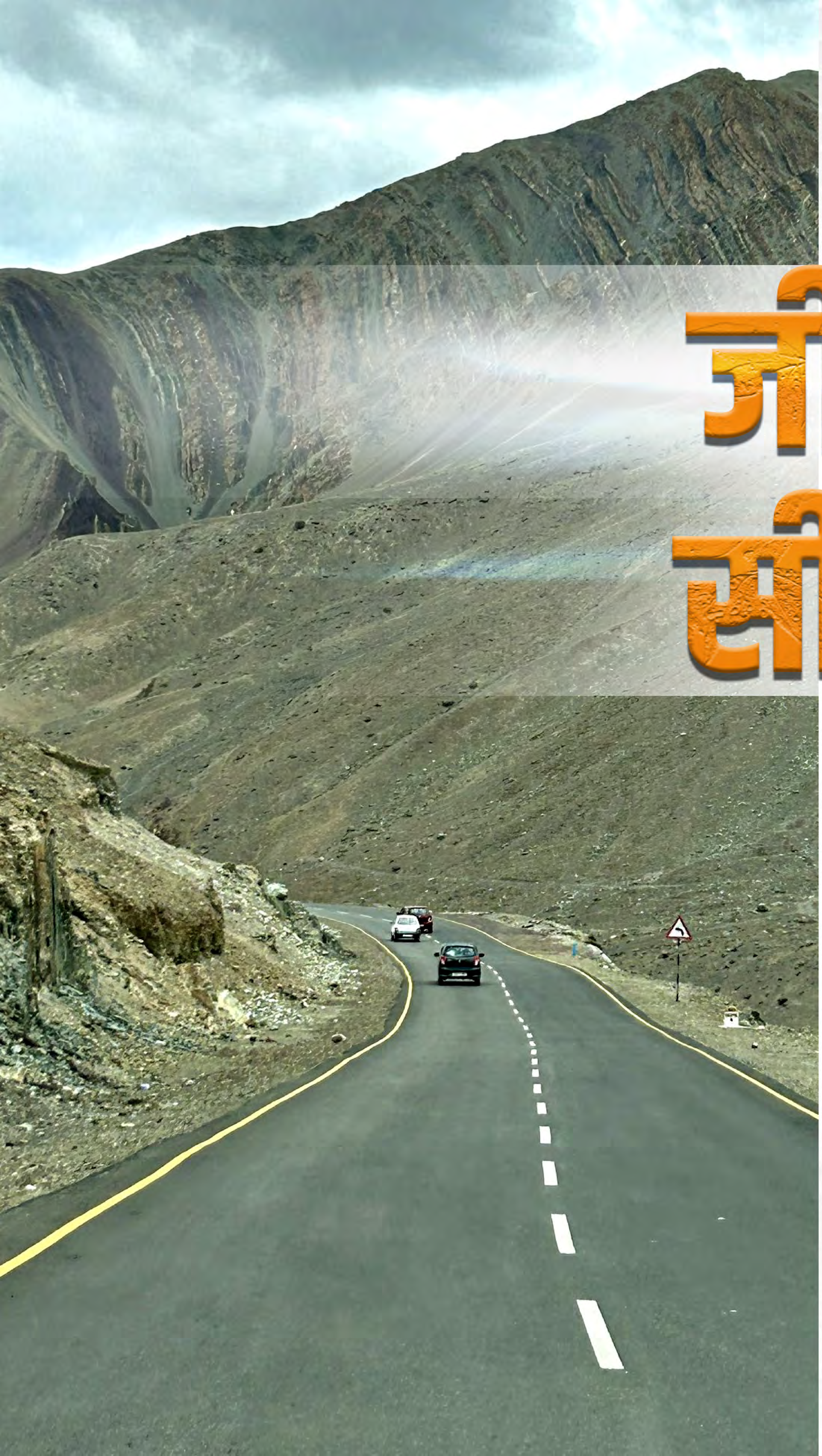

सुरक्षित भारत के लिए सीमा विकास

सीमा सड़क संगठन (BRO) ने अप्रैल 2014 से 6,700 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया है, जिसमें 1,400 किलोमीटर से अधिक की 32, भारत-चीन सीमा सड़कें और 5,300 किलोमीटर से अधिक की अन्य प्रमुख रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कें शामिल हैं।

2021-22 में, BRO ने 2022 तक कुल 102 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, 87 पुल और 15 सड़कें पूरी की गईं, इसके अलावा 103 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया गया।

रोहतांग में 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, अटल सुरंग का उद्घाटन अक्टूबर 2020 में किया गया था, ताकि इसके माध्यम लेह को वैकल्पिक मार्ग मिले और सभी मौसमों में इस मार्ग पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। इस टनल से मनाली और लेह के बीच की दूरी भी लगभग 46 किलोमीटर कम हुई है।

सुरक्षित भारत के लिए सीमा विकास

दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क: दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंग ला टॉप पर किया गया था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क सीमावर्ती गांवों (भारत-चीन सीमा) चिसुमले और डेमचोक को लेह को मुख्य सड़क से जोड़ती है।

सेला सुरंग का निर्माण: 13,960 फीट की ऊंचाई पर तवांगट को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बालीपारा-चरदुआर-तवांग रोड पर सेला सुरंग का निर्माण।

महिला अधिकारियों को मिला शीर्ष स्थान: बीआरओ के इतिहास में पहली बार, महिला अधिकारियों को इकाइयों की कमान सौंपी गई, जिसमें तीन सड़क निर्माण कंपनियां (आरसीसी) की वर्तमान में उनके द्वारा कमान संभाली जा रही हैं। बीआरओ ने जोशीमठ, उत्तराखंड में पहली बार सभी महिला ऑल वुमेन आरसीसी भी बनाई।

नई दिल्ली में बीआरओ मुख्यालय में सड़क सुरक्षा और जागरूकता के लिए उत्कृष्टता केंद्र और बेहतरीन सड़कों, पुलों, हवाई क्षेत्रों और सुरंगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले गए।

सैन्य बलों का वित्तपोषण

रक्षा बजट

- राष्ट्रीय सुरक्षा, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को मज़बूत करने के लिए 2014-15 से रक्षा बजट में 160% की वृद्धि।

वित्तीय वर्ष	रक्षा बजट (रक्षा पेंशन सहित)	पूंजीगत परिव्यय (आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास)
2014-15	2.29 लाख करोड़ रुपये	94,587 करोड़ रुपये
2015-16	2.47 लाख करोड़ रुपये	94,588 करोड़ रुपये
2016-17	2.49 लाख करोड़ रुपये	86,340 करोड़ रुपये
2017-18	3.60 लाख करोड़ रुपये	86,488 करोड़ रुपये
2018-19	4.04 लाख करोड़ रुपये	99,564 करोड़ रुपये
2019-20	4.31 लाख करोड़ रुपये	1.08 लाख करोड़ रुपये
2020-21	4.71 लाख करोड़ रुपये	1.18 लाख करोड़ रुपये
2021-22	4.78 लाख करोड़ रुपये	1.35 लाख करोड़ रुपये
2022-23	5.25 लाख करोड़ रुपये	1.52 लाख करोड़ रुपये
2023-24	5.94 लाख करोड़ रुपये	1.62 लाख करोड़ रुपये

- हथियारों और उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' विज़न को साकार करने के लिए, घरेलू निर्माताओं से ख़रीद के लिए रक्षा पूंजीगत परिव्यय में पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है। 2020-21 में 58% से 2023-24 में इसे बढ़ाकर 75% कर दिया गया है।

घरेलू उद्योगों में ख़रीद

वित्तीय वर्ष	पूंजी परिव्यय	प्रतिशत
2020-21	1.18 लाख करोड़ रुपये	58%
2021-22	1.35 लाख करोड़ रुपये	64%
2022-23	1.52 लाख करोड़ रुपये	68%
2023-24	1.62 लाख करोड़ रुपये	75%

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% निर्धारित करने के साथ उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास का क्षेत्र खोला गया। निजी उद्योग को स्पेशल पर्पज़ व्हिकल (एसपीवी) मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिज़ाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने और देश में रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) को वित्त वर्ष 2023-24 में 116 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह वित्त वर्ष 2022-23 से 93% अधिक है। इससे पहले यह आंकड़ा 60 करोड़ रुपये था। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में 45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 की तुलना में 95% अधिक है, पहले यह संख्या 23 करोड़ रुपये थी।

- केंद्रीय बजट 2023-24 में, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) का पूंजीगत बजट वित्त वर्ष 2022-23 में 3,500 करोड़ रुपये की तुलना में 43% बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो गया।

रक्षा पेंशन
ओआरओपी
'वन रैंक, वन पेंशन'

01 **वन रैंक वन पेंशन योजना:** पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग ओआरओपी लागू होने के साथ पूरी हो गई। इसका तात्पर्य यह है कि समान सेवा की अवधि के साथ एक ही रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा कर्मियों को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख़ कुछ भी हो।

02 7,123 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से, ओआरओपी लागू होने के बाद, आठ वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 57,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

03 **ओआरओपी का संशोधन:** 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को इस संशोधन के तहत कवर किया गया है।

04 25.13 लाख से अधिक (4.52 लाख से अधिक नए लाभार्थियों सहित) सशस्त्र बल पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं।

05 **स्पर्श पेंशन पोर्टल:** पेंशन दावों को संसाधित करने और बिना किसी बाहरी मध्यस्थ के सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन जमा करने के लिए एक वेब-आधारित प्रणाली शुरू की गई थी। स्पर्श पेंशन भोगी पहचान के लिए डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करता है, जिससे पेंशन भोगियों द्वारा पेंशन कार्यालयों में कई बार जाने की आवश्यकता को दूर किया जा सकता है।

06 स्पर्श पर लाभार्थियों की संख्या 11 लाख तक पहुंच गई है, जो कुल रक्षा पेंशनभोगियों का 33% है।

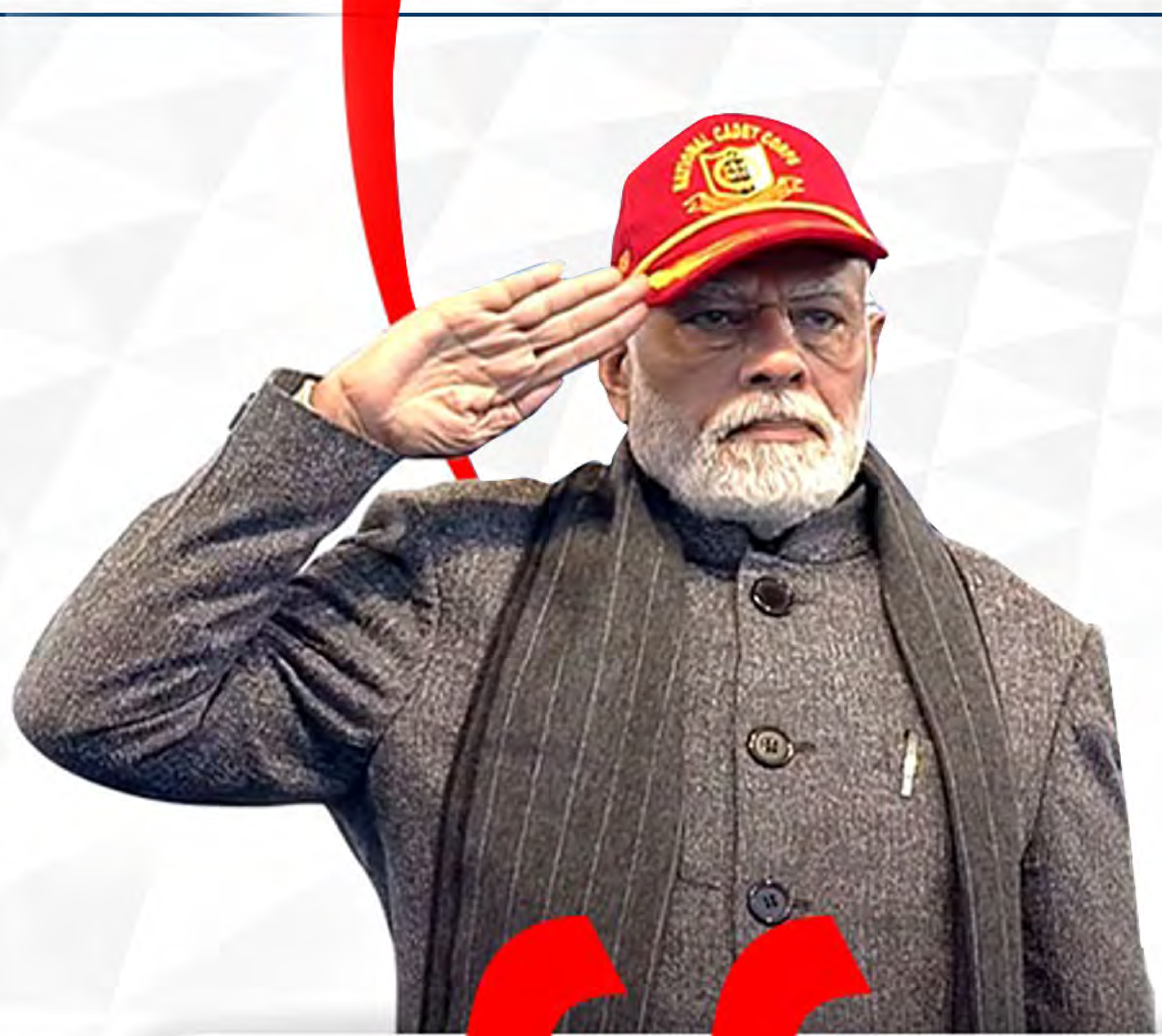

राष्ट्रीय कैडेट कोर वर्दी या एकरूपता के बारे में नहीं है,
यह एकता के बारे में है:

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
एनसीसी रैली, करियप्पा ग्राउंड, नई दिल्ली

युवाओं के नेतृत्व में विकास: सैनिक स्कूल और एनसीसी

- कक्षा 6 से शुरू होने वाले श्रेणीबद्ध तरीक़े से ग़ैर-सरकारी संगठनों/निजी/राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से 21 स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है।
- शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में मौजूदा और नए स्थापित स्कूलों में 1,602 से अधिक बालिका कैडेटों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया गया।
- पुनीत सागर अभियान: स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के समुद्री तटों को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान, दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था। एनसीसी के सभी 17 राज्य निदेशालयों के 1.5 लाख कैडेटों ने इसके तहत विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया।
- गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान पीएम एनसीसी रैली: सभी 17 राज्य एनसीसी निदेशालयों की टुकड़ियों ने 2022 और 2023 के दौरान मार्च पास्ट में भाग लिया।
- हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित माउंट युनम (6111 मीटर) के लिए 85 एनसीसी लड़कों और लड़कियों के पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई थी, एनसीसी लड़कों और लड़कियों ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

जनसंपर्क निदेशालय

रक्षा मंत्रालय

डी पी आर - एम.ओ.डी @ जी ओ वी डॉट इन

९ साल
उत्कृष्टता के